

सेमीकंडक्टर निवेश से प्रदेश में 4,450 रोजगार प्रस्तावित

पांच कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र, 9,625 करोड़ के निवेश की योजना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 का जापानी, ताइवानी और कोरियाई भाषाओं में विमोचन किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कंपनियों, स्टार्टअप तथा अनुसंधान संस्थानों के नवाचारों की जानकारी ली।

इस अवसर पर नीति की विशेषताओं पर केंद्रित दृश्य-श्रव्य फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश सेमीकॉन स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। आईआईटी इंदौर की दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित चैलेंज में 25 स्टार्टअप की प्रस्तुति के बाद 10 अंतिम प्रतिभागी चुने गए। विजेताओं को कुल छह लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।

समिट में पांच कंपनियों को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के आशय पत्र दिए गए। इनसे प्रदेश में 9,625 करोड़ रुपये का निवेश और 4,450 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित हैं। ग्वालियर के गंगा मालनपुर में



6,415 करोड़ रुपये से 50 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर, भोपाल में 2,000 करोड़ रुपये से लिथियम सेल विनिर्माण इकाई और इंदौर में 500 करोड़ रुपये से वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना है।

भोपाल और इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयां भी प्रस्तावित हैं। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने

कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन, चिप डिजाइन और अनुसंधान के लिए पांच संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में सात कंपनियों को कार्यालयीन स्थान के आशय पत्र दिए गए। इनसे 1,280 से अधिक रोजगार प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री ने 12 से अधिक

कंपनियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से निवेश पर चर्चा की। बैठकों में लगभग 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 10 हजार से अधिक रोजगार के प्रस्ताव मिले। प्रदर्शनी में 57 प्रदर्शकों ने 70 बूथ और तीन बड़े स्टॉल के माध्यम से तकनीक, स्वदेशी चिप और अनुसंधान कार्यों का प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री आज करेंगे नर्मदा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार, 24 अक्टूबर को धार जिले के सरदारपुर स्थित खेल परिसर में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर सूक्ष्म उद्‌हन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे।

परियोजना की लागत 2,387.60 करोड़ रुपये है। परियोजना से धार और झाबुआ जिलों के 260 गांवों की कुल 57,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का

लक्ष्य है। इसमें धार जिले की सरदारपुर तहसील के 66 गांवों की 25,422 हेक्टेयर भूमि और झाबुआ जिले के 194 गांवों की 32,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। झाबुआ जिले में झाबुआ तहसील के 108, पेटलावद के छह, मेघनगर के 28, थांदला के 39, रामा के 12 और राणापुर तहसील के एक गांव को परियोजना का लाभ मिलेगा।

परियोजना में भूमिगत पाइप नहर प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से 2.5 हेक्टेयर तक के

चक में 20 मीटर दबावयुक्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। किसान बूंद-बूंद और फुहार पद्धति से सिंचाई कर सकेंगे। इससे पानी के उपयोग में दक्षता बढ़ेगी और खेतों को समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

परियोजना के लिए धार जिले की कुशी तहसील के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी से 186.62 मिलियन घन मीटर जल का उद्‌हन प्रस्तावित है। योजना के संचालन के लिए 102.30 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।

पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में कराने की तैयारी

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में हो सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से एक-दो महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।

बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गरां में सरपंच समेलन के

दौरान मंत्री श्री पटेल ने बताया कि चुनाव से पहले पंचायत राज नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए एक महीने में अधिसूचना जारी करने और नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। ग्रामसभा की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन उसके अधिकार पंचायत समितियों को दिए जाएंगे। सरकार पंचायतों को नगरपालिका की तरह कर लगाने का अधिकार देने पर भी काम कर रही है। पंचायतें किन मदों में कर वसूल सकेंगी और दरें क्या होंगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मंत्री के अनुसार, प्रदेश में 2,472 पंचायत भवन बनकर तैयार हैं। इनका लोकार्पण 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया जाएगा। भवनों को दो मंजिला बनाए की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक के लिए 37.50 लाख रुपये दिए गए हैं। विभाग ने 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन भी बनवाए हैं।

ग्रामसभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने और पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देने पर काम

ग्रामीण अनुभवों के लिए मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण : राजा टी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पर्यटन सचिव एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलेया राजा टी ने पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव लेने के लिए मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया।

वे सिंगारपुर के सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल ट्रेड शो आईटीबी एशिया के नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टॉक सेशन को संबोधित कर रहे थे। 'रीडिस्ट्रिब्यूटिंग डिमांड थू



डिस्कवरी' विषय पर उन्होंने कहा कि कोविड के बाद यात्री नए अनुभवों और अनछुए पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने

के लिए मांग का पुनर्वितरण और नए गंतव्यों की खोज जरूरी है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में समृद्ध वन्यजीव, विरासत और कला के साथ 7 प्रमुख जनजातियां और 45 उप-जनजातियां हैं। प्रदेश में चंदेरी और महेश्वरी वस्त्रकला, गोंड चित्रकला तथा भोपाल की जरी-जरदोजी शिल्पकला की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने प्रदेश के टाइगर रिजर्व, पेंच के नेचर कॉक, ओरछा में बेतवा नदी की रिवर राफ्टिंग और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का भी उल्लेख किया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को अनूपपुर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आंदोलनों की आड़ लेकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के जरिए कांग्रेस की नीतियों और राजनीति को जनता के सामने रखेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस ईवीएम और संवैधानिक

आठ लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

नप्र, भोपाल : बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जियालाल अहिरवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के करीब आठ लाख आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। पत्र में सरकारी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान और सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करने की अपील की गई है।

बसपा ने स्थायी प्रकृति के कामों में लगे कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पद तय कर नियमित भर्ती नीति बनाने की मांग की है। पार्टी ने करीब आठ लाख कर्मचारियों का विभागवार सर्वे कराने और नियमित पदों की पहचान करने का सुझाव भी दिया है।

पत्र में न्यूनतम वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, पात्र कर्मचारियों को बोनस और अन्य वैधानिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। बसपा ने करीब पांच हजार ठेका और आउटसोर्स एजेंसियों के अनुबंधों की समीक्षा कर वेतन भुगतान तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान की जांच कराने की बात कही है। पार्टी ने ग्वालियर और नरसिंहपुर में कर्मचारियों को काम से हटाए जाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने की मांग भी की है।

मास्टर प्लान-2047 पर किसानों और व्यापारियों की आपत्ति

ज्ञापन सौंपा, मांगें नहीं मानीं तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरने की चेतावनी



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप को लेकर शुक्रवार को किसान और व्यापारी अपनी आपत्तियां दर्ज कराने शाहपुरा स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आए किसानों ने उपसंचालक हरिओम मोहेश्वरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव, बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और सरपंचों को बैठकों में नहीं बुलाने पर सवाल उठाए।

किसानों का कहना है कि प्रारूप में 66 गांवों की कृषि भूमि को नदी तट विकास, वन, हरित पट्टी और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे निजी जमीन, खेती और आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 के मास्टर प्लान में इन जमीनों का उपयोग कृषि के लिए निर्धारित था। बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण संबंधी प्रावधानों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। जनपद पंचायत अध्यक्ष फंदा प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि

वे मास्टर प्लान के खिलाफ हैं।

सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार ने आरोप लगाया कि योजना में शामिल सरपंचों को बैठकों में नहीं बुलाया गया। किसान गीता प्रसाद पाटीदार ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर टीएनसीपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे।

किसानों से पहले पहुंचे व्यापारियों ने व्यावसायिक भू-उपयोग, निर्माण क्षेत्र अनुपात, रूपांतरण शुल्क और सीलिंग कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने रूपांतरण शुल्क एकमुश्त पांच प्रतिशत तय करने, शुल्क जमा करने पर पूरा व्यावसायिक निर्माण क्षेत्र अनुपात देने और पुराने बाजारों को राहत देने की मांग की। टीएनसीपी की संयुक्त संचालक इंदू त्रिपाठी ने बताया कि नियमानुसार 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त आपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज करने के बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

69 कार्यों का भूमिपूजन और 32 का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 28 अक्टूबर के इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में 5,519.05 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें 3,660.89 करोड़ रुपये के 69 कार्यों का भूमिपूजन और 1,858.16 करोड़ रुपये के 32 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,336 आवासीय इकाइयों से जुड़े 1,359.22 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन होगा। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के तीन कार्यों का भूमिपूजन और 14 कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कम्प्रेस्ड बायोगैस और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के पांच कार्यों का 342.71 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया जाएगा। उपयोग किए गए जल के प्रबंधन से जुड़े 37 कार्यों पर 277.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

केरवा डैम की सीमा और अतिक्रमणों का निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केरवा डैम की सीमा और आसपास के अतिक्रमणों की स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को मौके का निरीक्षण किया। टीम अब शुक्रवार को रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे अधिकरण में प्रस्तुत किया जाएगा।

एनजीटी ने जलाशय के पूर्ण जलस्तर (एफटीएल) और उसके बफर क्षेत्र का अंतिम निर्धारण उपलब्ध सरकारी अभिलेखों, जमीनी सत्यापन और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड का उपयोग करने को कहा है। विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाएगी। सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, केरवा डैम का जलमान क्षेत्र करीब 462.150 हेक्टेयर है।

एनजीटी के निर्देश पर टीम ने किया जमीनी सत्यापन
रिपोर्ट अगली सुनवाई में होगी पेश

करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी को यह प्रक्रिया तीन सप्ताह में पूरी करनी है। अधिकरण ने एफटीएल और बफर क्षेत्र तय करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रों, जमीनी सत्यापन और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड का उपयोग करने को कहा है। विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाएगी। सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, केरवा डैम का जलमान क्षेत्र करीब 462.150 हेक्टेयर है।

इसकी सीमा 1,080 कंक्रीट ब्लॉकों और खंभों से चिह्नित की गई थी। निरीक्षण के दौरान टीम यह भी देखेगी कि इनमें से कितने सीमा-चिह्न मौके पर मौजूद हैं। पहले की जांच में जलाशय क्षेत्र में 33 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। इनमें 18 सरकारी भूमि और 15 निजी भूमि से जुड़ी संरचनाएं बताई गई थीं। अब ड्रोन सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन से यह पता लगाया जाएगा कि पहले चिह्नित अतिक्रमणों में से कितने वर्तमान में मौजूद हैं और उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। टीम की रिपोर्ट में एफटीएल और बफर क्षेत्र के निर्धारण के साथ निरीक्षण के निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर पुस्तकों के लेखन को दिशा देंगे विशेषज्ञ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा की पाठ्यसामग्री में शामिल करने तथा प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण साहित्य तैयार करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की दो दिवसीय कार्यशाला 24 और 25 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित होगी। शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर स्वशास्त्री महाविद्यालय में होने वाली कार्यशाला में उच्च

शिक्षा मंत्री इंंदर सिंह परमार उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर की पाठ्यसामग्री के लेखन पर चर्चा होगी। विषय विशेषज्ञ भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रामाणिक स्रोतों, ऐतिहासिक आधारों और विभिन्न शैक्षणिक विषयों के साथ उसके समन्वय पर विचार-विमर्श करेंगे। पुस्तक लेखन की कार्यविधि, संदर्भ सामग्री, भाषा-शैली और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी

अध्ययन सामग्री तैयार करने पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास सहित विभिन्न विषयों की पाठ्यसामग्री, प्रश्नों, गतिविधियों और अभ्यासों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत को अकादमिक अध्ययन से जोड़ते हुए व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें तैयार करना है।

बैठक

संगठन महामंत्री ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान पर दिया जोर...

कार्यकर्ता कांग्रेस की राजनीति जनता के सामने उजागर करें



संस्थाओं पर सवाल उठाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन मुद्दों पर जनता के बीच तथ्यपरक संवाद करने और संगठन की विचारधारा

पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद और घुसपैठ के विरुद्ध कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों का

भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि देश और समाज के हित में काम करना है। जनसेवा,

गरीब कल्याण और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय रहने की अपील करते हुए उन्होंने सेवा संकल्प अभियान में अनूपपुर जिले के प्रदेश में 14वें स्थान पर आने पर कार्यकर्ताओं की सराहना की। बैठक को संभाग प्रभारी गौरव सिरोटिया और जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री दिलीप अहिरवार, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चवाड़ा, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक विसाहदलाल सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।